



भारत को आशंका है, ईरान “स्ट्रेट ऑफ होरमुज़” में जहाजों का आवागमन प्रतिबंधित करेगा

भारत विश्व में ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा “कंज़्यूमर” है तथा अपनी खपत का 60 प्रतिशत ऑयल खाड़ी देशों से आयात करता है, जिसे “स्ट्रेट ऑफ होरमुज़” से होकर गुजरना होता है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 जून। इज़रायल-ईरान संघर्ष एक नए तथा नाजुक चरण में प्रवेश कर रहा है, जहाँ अमेरिकी हवाई हमले ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इससे इस्लामिक गणराज्य अब निर्णायक प्रतिक्रिया के करीब आ गया है। हालाँकि पूर्ण पैमाने पर युद्ध की संभावना कम है, लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया लगभग निश्चित रूप से पारंपरिक नहीं होगी, बल्कि यह प्राँक्सि युद्ध, साइबर हमलों और, सबसे चिंताजनक रूप में, फारस की खाड़ी में रणनीतिक व्यवधान के रूप में सामने आ सकती है। इन चिंताओं में सबसे प्रमुख है, होरमुज़ स्ट्रेट (जलडमरूमध्य) को बंद करने या उसे अवरूद्ध किये जाने की संभावना, चाहे वह वास्तविक हो या प्रतीकात्मक। यदि ऐसा होता है, तो भारत उन पहले देशों में होगा, जो इसका असर महसूस करेंगे।

- इन हालात में “ऑयल की सप्लाई” में जरा भी रूकावट होने से भारत की इकॉनमी डांवा-डोल हो सकती है।
- ईरान, संभवतया नौसैनिक अभ्यास, ड्रोन व मिसाइल एटैक की धमकी और लैंड माइन्स बिछाने की कार्यवाही आदि से, जहाजों के आवागमन को बाधित कर सकता है।
- यह भी माना जा रहा है कि ईरान “स्ट्रेट ऑफ होरमुज़” से जहाजों के आवागमन को बंद नहीं करेगा, क्योंकि टोटल आवागमन बंद करने से तो ईरान स्वयम् भी अपना “ऑयल” अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में नहीं बेच पायेगा।
- केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ज़रूर हॉसला ऊँचा रखने के लिए कहा कि गत कुछ वर्षों में भारत ने खाड़ी देशों के अलावा भी कई अन्य विकल्प ढूँढ़े हैं, ऑयल खरीदने के लिए। पर, फिर भी तेल विशेषज्ञों का मानना है कि ऑयल व गैस काफी संवेदनशील सेंक्टर है तथा लंबे समय तक ऑयल व गैस की सप्लाई बाधित होने से भारत की इकॉनमी में भारी अस्थिरता पैदा होगी।

होरमुज़ स्ट्रेट, जो सबसे सँकरे बिंदु पर केवल 21 मील चौड़ा है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग है। प्रतिदिन वैश्विक व्यापार वाले लगभग 20 प्रतिशत तेल का प्रवाह इसी मार्ग से होता

है। हालाँकि ईरान के द्वारा इस मार्ग को पूरी तरह से बंद करने की संभावना कम है, क्योंकि इससे उसके अपने तेल निर्यात पर असर पड़ेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हो सकती

है, इसलिए वह सीमित व्यवधान की रणनीति अपना सकता है: नौसैनिक अभ्यास, वाणिज्यिक टैंकरों को परेशान करना, ड्रोन या मिसाइलों की धमकी, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लालू यादव ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिये नामांकन भरा

पटना, 23 जून। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव के लिए आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

यादव ने सोमवार को राजद के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी डॉ. रामचंद्र पूर्वं और सहायक निर्वाचन अधिकारी वितरंजन गगन के समक्ष चार सेटों में

- वे 24 जून को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित होंगे तथा 5 जुलाई को राष्ट्रीय परिषद उनके निर्वाचन की पुष्टि करेगी।

नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रत्येक सेट में दस प्रस्तावकों के हस्ताक्षर हैं। इन प्रस्तावकों में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, वरिष्ठ नेता शिवानंद विश्वारी सहित अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं।

गगन ने बताया कि नामांकन पत्रों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुबोध अग्रवाल ने आरएफसी सीएमडी का पद संभाला



सुबोध अग्रवाल

जयपुर, 23 जून (कासं)। राजस्थान के सबसे वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने सोमवार को राजस्थान वित्त निगम जयपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। इससे पूर्व, वे इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान

- कुलदीप रांका, अखिल अरोड़ा, भास्कर सावंत ने भी कार्य भार ग्रहण किया।

जयपुर में महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1988 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी हैं।

इसी प्रकार, वर्ष 1994 बैच के आई.ए.एस. कुलदीप रांका ने भी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव, 1993 बैच के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केजरीवाल, पंजाब का मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं?

चर्चाओं के अनुसार, वे पंजाब की असैम्बली के स्पीकर को मु.मंत्री बनाकर, वर्तमान मु.मंत्री मान को राज्यसभा भेज सकते हैं, जैसा कि विदित ही है, वर्तमान स्पीकर ज्ञानी ज़ैल सिंह के पोते हैं

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 जून। हाल ही में हुए उपचुनावों के मिश्रित नतीजे सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी को गुजरात और पंजाब से एक-एक सीट मिली है। कांग्रेस को केरल से, भाजपा को गुजरात से, तृणमूल कांग्रेस को प.बंगाल से एक-एक सीट मिली है।

कांग्रेस को केरल में यह सीट मिलने की उम्मीद पहले से ही थी, यह सीट 35 साल से कांग्रेस के पास थी। पार्टी ने यहां से वाममोर्चा को हराया है। गुजरात में आप ने पहले भी वसावदरा सीट जीती थी, पर यहां के विधायक भाजपा में शामिल हो गये थे। दुबारा हुए उपचुनाव में आप ने फिर से यह सीट जीत ली और दूसरी सीट भाजपा को मिली।

क्या यह गुजरात में भाजपा के लिए चेतावनी का संकेत है, क्या गुजरात भाजपा के हाथ से निकल रहा है?

लेकिन असली कहानी तो पंजाब में है। यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग विधायक की कुर्सी छोड़कर

- कांग्रेस आपसी मतभेदों व खींचतान में इतनी उलझी है कि प्रदेशाध्यक्ष राजा वडिंग अपना विधायक पद छोड़कर जब लुधियाना से सांसद बने तो उनकी पत्नी ने उनकी विधायक सीट, लुधियाना वैस्ट, से चुनाव लड़ा था और हार गई थीं और अब लुधियाना पश्चिम की सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई है और इस सीट से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीता।

सांसद बन गए। इस सीट से उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। अब कांग्रेस लुधियाना वैस्ट सीट भी हार गई है। वह सीट, जहाँ उपचुनाव हुआ, राजा वडिंग की लुधियाना लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगभग एक प्रतिशत कम हुआ।

इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण आशु थे, जो चरणजीत सिंह चन्नी और राजा गुरजीत के करीबी माने जाते हैं। पार्टी में अंदरूनी कलह के चलते मोर्चे का समर्थन किया हुआ और आम आदमी पार्टी ने यह सीट जीत ली।

ऐसी जोरदार अटकलें हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं। चर्चा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को राज्यसभा भेजा जा सकता है, क्योंकि वहाँ एक सीट खाली है। उनकी जगह विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाए जाने की योजना है, जो पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह के पोते हैं।

इस जीत के बाद, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद, जब पार्टी को लगभग खारिज ही कर दिया गया था।

अपेक्षित से ही रहे उपचुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी को दो सीटें तथा कांग्रेस, भाजपा व तृणमूल को एक-एक सीट पर विजय मिली

- आप के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा में एट्री का रास्ता खुला।
- राज्यसभा में आप के सांसद संजीव अरोड़ा, लुधियाना वेस्ट से विधायक चुने गये हैं। अतः अब वे अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा देंगे, उन्होंने अपने नेता केजरीवाल को राज्यसभा में भेजने का रास्ता खोल दिया है।

दिया है। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, “गुजरात की जनता अब भाजपा से परेशान हो चुकी है और आम आदमी पार्टी में आशा देख रही है।”

यह स्पष्ट होता जा रहा है कि केजरीवाल खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर रहे हैं, जिससे यह मोर्चा कमजोर हो रहा है।

केरल की नीलांबुर सीट कांग्रेस के खाते में गई, भाजपा ने गुजरात की सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी, जबकि पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने सहजता से जीत दर्ज की।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर

लिखा, कालीगंज विधानसभा उपचुनाव में सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। मैं सिर झुकाकर उनका आभार प्रकट करती हूँ। इस जीत की निर्माता जनता है। कालीगंज के मेरे सभी सहयोगियों ने इस जीत के लिए पूरी मेहनत की। मैं उन्हें बधाई देती हूँ। यह उपचुनाव टीएमसी विधायक नसीरुद्दीन अहमद के निधन के बाद कराया गया था।

देश के अन्य तीन विधानसभा क्षेत्रों में स्थिति यथावत रही, सिवाय केरल के नीलांबुर के, जो वायनाड लोकसभा सीट का हिस्सा है, जहां से प्रियंका गांधी वाड़ा सांसद हैं।

नीलांबुर में जीत के प्रति आश्चर्य प्रियंका गांधी वाड़ा ने इसका श्रेय टीम वर्क को दिया।

उन्होंने लिखा, हमने एक टीम के रूप में काम किया, समर्पण और एकाग्रता के साथ, यही इस सफलता का सबसे बड़ा सबक है। मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए उन्होंने लिखा, “संविधान के मूल्यों और यूडीएफ के प्रगतिशील दृष्टिकोण में आपका विश्वास हमारे आगे के मार्ग का मार्गदर्शक रहेगा।

कांग्रेस प्रत्याशी आर्यादत्त शौकत इस सीट से सीपीएम के एम. स्वराज से 11,077 वोटों से आगे चल रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों में इस सीट से निर्दलीय पी.वी. अन्वर विजयी हुए थे, जिन्होंने बाद में वाम मोर्चे का समर्थन किया था। लेकिन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मतभेद के चलते, अन्वर ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और बाद में तृणमूल कांग्रेस की केरल इकाई में शामिल हो गए थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को आजीवन कारावास

जयपुर, 23 जून। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बाबूलाल जाट को आजीवन कारावास की सजा

- पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी ने सजा के साथ साठ हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

सुनाई है। साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में नाबालिगों के प्रति ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 जून। जैसे-जैसे दुनिया बढ़ते हुए भू-राजनीतिक तनावों से जूझ रही है-चाहे वह लंबे समय से चल रहा रूस-यूक्रेन युद्ध हो या तेजी से फैलता ईरान-इज़राइल संघर्ष, भारत की विदेश नीति सम्बंधी रुख को लेकर उसकी आलोचना हो रही है हालाँकि कुछ लोग इसे रणनीतिक चुपों कह रहे हैं।

जहाँ अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ और रूस जैसी वैश्विक शक्तियां खुलकर अपने रुख या हित व्यक्त कर रही हैं, वहीं भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक उभरती वैश्विक शक्ति है, ने अधिकतर मामलों में मतदान से दूर रहने या तटस्थ बयानों

को प्राथमिकता दी है। भारत के एक शीर्ष पूर्व राजनयिक ने, नाम न छापने की शर्त पर, कहा, “यह शायद स्वतंत्रता के बाद पहला अवसर है, जब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में भारत की कोई अर्थपूर्ण या सक्रिय भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। यह केवल चुपों नहीं है, यह अनुपस्थिति है।”

भारत ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया से संबंधित कई महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर मतदान से परहेज किया है। जहां अधिकारी इसे रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की आवश्यकता बताते हैं, वहीं आलोचकों का कहना है कि यह कूटनीतिक संतुलन प्रक्रिया अब निष्क्रिय मुद्रा में बदल गई है, जिससे भारत की वैश्विक प्रभावशीलता और

- भारत की विदेश नीति के आलोचक कहते हैं आजादी के बाद, पहली बार ऐसा लग रहा है कि आज के समय की सबसे बड़े वैश्विक राजनीतिक संकट के समय, भारत की कोई रचनात्मक भूमिका नहीं है।

- इन आलोचकों का यह भी कहना है कि कूटनीति की दृष्टि से संतुलन बैठाने के चक्कर में भारत धीरे-धीरे निष्क्रिय होकर न केवल समय के साथ बाहर रहा है बल्कि भारत का प्रभाव घटता जा रहा है और उसकी नैतिक नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता भी कम हो रही है।

नैतिक अधिकार दोनों में गिरावट आई है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह परिवर्तन मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं में बदलाव का परिणाम है। विदेश नीति मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अनुराधा

सेन के अनुसार, यह केवल तटस्थता नहीं है, बल्कि भारत की ऐतिहासिक नैतिक दिशा से एक सुनियोजित तरीके से पीछे हटना है। नेहरूवादी सिद्धांतों के तहत, भारत ने उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों,

निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का समर्थन किया। लेकिन हाल के कदमों से संकेत मिलता है कि भारत अब दीर्घकालिक वैश्विक दृष्टिकोण के बजाय, अल्पकालिक एवं तात्कालिक हितों से प्रेरित लेन-देन आधारित कूटनीति की ओर बढ़ रहा है। ईरान-इज़रायल संघर्ष, जो समूचे खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है, ने भारत के लिए एक बड़ी दुविधा पैदा कर दी है। खाड़ी देशों में 80 लाख से अधिक भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं, ऐसे में किसी भी प्रकार का तनाव आर्थिक और मानवीय दोनों दृष्टियों से गंभीर परिणाम ला सकता है। फिर भी भारत ने अब तक केवल “तनाव कम करने” की अपील की है, बिना किसी ठोस कूटनीतिक पहल या

मध्यस्थता की भूमिका के, जो पहले भारत पश्चिम एशिया संकटों में निभाता रहा है।

इसी प्रकार, रूस-यूक्रेन युद्ध ने भी भारत की विदेश नीति की सीमाओं को उजागर किया है। भारत, जो रियायती रूसी तेल खरीदता है और रूस से रक्षा संबंध बनाए रखता है, अपनी इस स्थिति का उपयोग किसी महत्वपूर्ण शांति प्रयास या मध्यस्थ भूमिका निभाने हेतु करने में विफल रहा है।

एक विश्लेषक के शब्दों में, यहां तक कि ग्लोबल साउथ (वैश्विक दक्षिण) भी अब नैतिक एवं कूटनीतिक नेतृत्व के लिए ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और यहां तक कि तुर्की की ओर देख रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान ने कतर व इराक के अमेरिकन बेस पर हमला किया

तेहरान/तेल अवीव। ईरान ने सोमवार को कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दाग दी। यह हमला अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हालिया हवाई हमलों के जवाब में किया गया। ईरानी मीडिया के अनुसार, कतर के अल उदेद एयर बेस पर छह मिसाइलें और इराक के ऐन अल-असद बेस पर एक

- अमेरिका ने कहा, हमले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। कतर सरकार ने ईरानी हमले की कड़ी निंदा की।

मिसाइल दागी गई। इन हमलों को विजय की घोषणा नामक अभियान का हिस्सा बताया गया।

हालाँकि, कतर में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले का कोई